राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 4848/2023

नाथू राम गोयल पुत्र शिव लाल गोयल, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी, गोयलों का मौहल्ला, ग्राम नापासर, तहसील एवं जिला बीकानेर, राजस्थान----याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव के माध्यम से, राजस्थान राज्य, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर.

4. निदेशक (पेंशन), पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, जयपुर राजस्थान।

5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, बीकानेर.----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री निशंक मधान।
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री रवि पंवार, प्रमेंद्र बोहरा।

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

30/01/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांकित 13.03.2023 (अनुलग्नक-5), एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसे उत्तरदाताओं ने अस्वीकार कर दिया। याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन और उसे उसके सेवानिवृत्ति लाभों और पेंशन से वंचित कर दिया गया।

2. याचिकाकर्ता, जिसे शुरू में 01.03.1998 को शिक्षक ग्रेड-III के रूप में नियुक्त किया गया था, 31.08.2020 को सेवानिवृत्त हो गया। हालाँकि, सेवानिवृत्ति के बाद भी, याचिकाकर्ता को उसका सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी, पीएफ, लीव इनकैशमेंट, एटीसी और पेंशन नहीं मिला है।

3. याचिकाकर्ता ने शुरू में विभाग से संपर्क किया, ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने पहले एक रिट याचिका (S.B. CWP No.6174/2021) दायर की, इस याचिका का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2021 को किया गया। विभाग को याचिकाकर्ता के विरोध-पत्र पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

4. अदालत के निर्देश के बावजूद, विभाग ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय नहीं लिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 27.08.2021 को वकील के माध्यम से एक कानूनी नोटिस भेजा। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

5. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 06.10.2021 को अवमानना याचिका दायर की, जो विचाराधीन है। इस समय के दौरान, 13.03.2023 को, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया, जिससे वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

6. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से संबोधित वे तर्क भी शामिल हैं जो खुद को याचिकाकर्ता की वर्तमान पत्नी होने का दावा करते हुए अभियोग की मांग कर रहे हैं।

7. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता गंभीर वैवाहिक कलह से गुजर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप चल रही कानूनी कार्यवाही और अदालत के आदेशों में याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी को मासिक भरण-पोषण का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जो अपने भरण-पोषण बकाया के माध्यम से सेवानिवृत्ति लाभों का दावा भी कर रही है।

8. हालांकि, वैवाहिक मुद्दों का समाधान उपयुक्त सक्षम अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिकाकर्ता की पत्नी निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से या सक्षम अदालत से संपर्क करके अदालत के आदेशों को लागू करने की मांग करने की हकदार है यदि आदेश के अनुसार रखरखाव का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

9. यहाँ पर्याप्त है कि जब तक कोई सक्षम अदालत याचिकाकर्ता को उसकी अलग हो चुकी पत्नी के हितों के कारण पेंशन लाभ वितरित करने से विभाग को रोकने के लिए विशिष्ट आदेश जारी नहीं करती है, तब तक इस तरह के विचार विभाग के कार्यों में बाधा नहीं बन सकते हैं।

10. एक अदालती प्रश्न के उत्तर में, यह स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई अदालती आदेश मौजूद नहीं है।

11. इसके अलावा, उत्तरदाताओं के वकील को प्रासंगिक सेवा नियमों का हवाला देने के लिए भी कहा गया था जो विभाग को लंबित वैवाहिक विवाद या उनकी मृत्यु के बाद कर्मचारी के नामांकित

व्यक्ति के बारे में अनिश्चितता के कारण पेंशन लाभों को रोकने के लिए सशक्त बनाते हैं।

12. वकील का जवाब था कि हालांकि ऐसा कोई सेवा नियम नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से अपनी नामित पत्नी को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में नामित किया है, जिसके साथ वह अपनी पहली पत्नी से तलाक प्राप्त किए बिना पुनर्विवाह करने का दावा करता है।

13. इन परिस्थितियों के आलोक में, यह याचिकाकर्ता, उसकी अलग हो चुकी पत्नी और उसकी वर्तमान पत्नी के बीच विवाद प्रतीत होता है, जिसने अपनी पहली शादी के विघटन के बिना उससे शादी की है।

14. याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, विशेष रूप से पारिवारिक अदालत में चल रही मुकदमेबाजी को देखते हुए, वित्तीय लाभ के लिए अपनी अलग हो चुकी पत्नी को नामित करने से बचना शायद उसके लिए उचित है।

15. चाहे जो भी हो, इक्विटी को संतुलित करने के लिए, यह उचित समझा जाता है कि विभाग याचिकाकर्ता के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दायर लंबित मामलों को एक बाधा के रूप में विचार किए बिना उसके पेंशन लाभों के वितरण के साथ आगे बढ़े, बशर्ते कि वह अन्यथा उन्हें प्राप्त करने का हकदार हो।

16. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है, जिसमें 13.03.2023 (अनुलग्नक-5) के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों के वितरण के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा अभियोग के लिए दायर आवेदन का भी निपटारा किया जाता है, इस टिप्पणी के साथ कि वह याचिकाकर्ता से अपने रखरखाव और अन्य बकाया के लिए उचित कानूनी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि कानून द्वारा अनुमति दी गई है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।